



H5  
17/10/89

# भारत का राजापत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (१)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 570] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1988/कार्तिक 10, 1910  
No. 570] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1988/KARTIKA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह भवनालय

(1)

(2)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

मा. का. नि. 1052(प्र) :- केंद्रीय मरकार, पंजाब पुनर्गठन प्रधि-  
नियम, 1966 (1966 का 31) वी. धारा 87 द्वारा प्रदत्त शब्दों  
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की लारीब को पंजाब राज्य में  
यथाप्रवृत्त इसल उत्तराधिकारी के स्वतंत्र (1) में विविधिट प्रधि-  
नियमितियों को, अन्तु वी के स्वतंत्र (2) में की नस्त्यानी प्रधिनियमों में  
विविधिट उत्तरानों के अवीत रहने द्वारा, पंजाब राज्य शब्द को  
विस्थापित करती है।

प्रभागी

अधिनियमिति

उपलब्ध

(1)

(2)

1. पंजाब साधारण विधाय-कर  
(मंगोधन) विधिनियम, 1973  
(1973 का पंजाब अधिनियम  
म. 11)

1. धारा 2 में, "पंजाब साधारण  
विधाय-कर अधिनियम, 1948",  
ग्रन्थी और अंकों के स्थान पर  
"चंडीगढ़ संघ राज्य शेष में यथा-

2. पंजाब साधारण विधाय-कर दूसरा (संगोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का पंजाब अधिनियम म. 29)	2. प्रांत 3 का सोप किया जाएगा। धारा 2 में, "पंजाब साधारण विधाय-कर अधिनियम, 1948" ग्रन्थी और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य शेष में यथा- प्रवृत्त पंजाब साधारण विधाय- कर अधिनियम, 1948" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
3. पंजाब साधारण विधाय-कर (मंगोधन और विधिमास्यकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का पंजाब अधिनियम म. 11)	1. धारा 1 में, उपधारा (2) का नाप किया जाएगा। 2. धारा 2 में, "पंजाब साधारण विधाय-कर अधिनियम, 1948" ग्रन्थी और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य शेष में यथा- प्रवृत्त पंजाब साधारण विधाय- कर अधिनियम, 1948" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(1)	(2)	(1)	(2)
	<p>प्रधिनियम, 1948" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;</p> <p>(ii) "और सैवें हुआ समझा जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।</p> <p>3. धारा 3 में, "और सैवें हुआ समझा जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।</p> <p>4. धारा 4 और धारा 5 का लोप किया जाएगा ।</p>		<p>"चंडीगढ़ संघ राज्य सेक्रेटरी में पश्च-प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर प्रधिनियम, 1948" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।</p> <p>3. धारा 5 में, "राज्य मरकार" शब्दों के स्थान पर "मंत्रिमंत्री" के प्रतीक 239 के अधीन राज्य-पति, द्वारा नियुक्त प्रशस्तक" शब्द रखे जाएंगे ।</p>
			उपाधन-१
4. पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) प्रधिनियम, 1978 (1978 का पंजाब प्रधिनियम सं. 2)	<p>1. धारा 1 में, उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।</p> <p>2. धारा 2 में, "पंजाब साधारण विक्रय-कर प्रधिनियम, 1948" शब्दों और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य सेक्रेटरी में पश्च-प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर प्रधिनियम, 1948" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।</p> <p>3. धारा 3 में, (i) "मंत्री, 1973 के पहले विन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) प्रधिनियम, 1978 के चंडीगढ़ संघ राज्य सेक्रेटरी की विस्तारित किए जाने की तारीख" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।</p> <p>(ii) "राज्य" शब्द के स्थान पर, जहाँ जहाँ वह धारा 4 "चंडीगढ़ संघ राज्य सेक्रेटरी" शब्द रखे जाएंगे ।</p> <p>4. धारा 5 में, "पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) प्रधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व" शब्दों, अंकों और कोठकों के स्थान पर जहाँ जहाँ वह भासते हैं, "पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) प्रधिनियम, 1978 के चंडीगढ़ संघ राज्य सेक्रेटरी के विस्तारण के पूर्व" शब्द, कोठक और अंक रख जाएंगे ।</p> <p>5. धारा 8 और 9 का लोप किया जाएगा ।</p>	<p>पंजाब साधारण विक्रय-कर प्रधिनियम, 1973 (1973 का पंजाब प्रधिनियम सं. 14)।</p> <p>पंजाब साधारण विक्रय-कर प्रधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए प्रधिनियम ।</p> <p>भारत गणराज्य के खींचीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विभान-गंडल द्वारा निर्माणित रूप में वह प्रधिनियमित हो :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संक्षिप्त नाम—इस प्रधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन) प्रधिनियम, 1973 है ।</li> <li>2. 1948 के पंजाब प्रधिनियम 66 की धारा 4 का संशोधन-चंडीगढ़ संघ राज्य सेक्रेटरी में पंजाब साधारण विक्रय-कर प्रधिनियम, 1948 की उपधारा (5) में,— <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) खंड (खंड) में, "25,000 रुपये" अंकों और शब्द के स्थान पर, "40,000 रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे; और</li> <li>(ii) खंड (खंड) में, "40,000 रुपये" अंकों और शब्द के स्थान पर "1,00,000 रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।</li> </ul> </li> </ol>	उपाधन-१
5. पंजाब साधारण विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) प्रधिनियम, 1978 (1978 का पंजाब प्रधिनियम सं. 26)	<p>चंडीगढ़ संघ राज्यसेक्रेटरी पर पंजाब साधारण विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) प्रधिनियम, 1973 (1973 का पंजाब प्रधिनियम सं. 29)</p>	<p>उपाधन-२</p> <p>पंजाब साधारण विक्रय-कर प्रधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए प्रधिनियम ।</p> <p>भारत गणराज्य के खींचीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विभान-गंडल द्वारा निर्माणित रूप में वह प्रधिनियमित हो :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संक्षिप्त नाम—इस प्रधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) प्रधिनियम, 1973 है ।</li> <li>2. 1948 के पंजाब प्रधिनियम 66 में नई धारा 3 का अन्त-स्थापन :—चंडीगढ़ संघ राज्यसेक्रेटरी में पंजाब प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर प्रधिनियम, 1948 की धारा 3 के पश्चात् निर्माणित धारा अंक संशोधन की जाएगी, अर्थात् :—</li> </ol>	उपाधन-२
	<p>"इक. प्रतिशिक्षित कर का उत्पत्तण—(1) इस प्रधिनियम में किसी वान के होते हुए भी, किसी धोकानी फौ कराई या भावक्षण पर प्रतिशिक्षित कर जो उसके द्वारा इस प्रधिनियम के प्रधीन देय कर के दो प्रतिशत की दर से संगणित किया जा ॥ ॥, उड्डानी और संपर्कित किया जाएगा ।</p>		

परन्तु इस अधिनियम के अधीन वेय संकलित कर और अधिभार ऐसे माल को बाबत जिसे केंद्रीय विभाग-कर अधिनियम, 1956 द्वारा 14 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बाणिज्य में विशेष महत्व का घोषित किया गया है, उस अधिनियम की धारा 15 द्वारा नियत दर से अधिक नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपरांत, जहाँ तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन उद्यग्हणीय प्रतिरिक्षन दर के संबंध में ऐसे लाग़ होते जैसे वे इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उद्यग्हणीय कर के संबंध लाग़ होते हैं।

#### उपांश्च—3

बंडीगढ़ संघ राज्यक्रम को व्याविस्तारित पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विभिन्नात्मकरण) अधिनियम, 1979 (1979 का पंजाब अधिनियम सं. 11)

पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उत्तरांशद्वे वर्ष में पंजाब राज्यविधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. भक्षित नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संशिष्ट नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विभिन्नात्मकरण) अधिनियम, 1976 है।

2. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 5 का संशोधन :—बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 5 के पहले परस्तुक में, “विनाम-वस्तुओं” शब्द का लाप किया जाएगा।

3. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 से उपबंध प्रत्यक्षी के का संशोधन :—मूल अधिनियम में उपबंध प्रत्यक्षी के में “विनाम-वस्तुएं” शब्द का लाप किया जाएगा।

#### उपांश्च—4

बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विभिन्नात्मकरण) अधिनियम, 1978 (1978 का पंजाब अधिनियम संशोधन 2)

पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उत्तरांशद्वे वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विभिन्नात्मकरण) अधिनियम, 1978 है।

2. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 का संशोधन :—बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) “भूमिक उत्पादक और करान्दान अधिकारी” काल्डों के स्थान पर जहाँ जहाँ वे भालते हैं, “उत्पादक और करान्दान अधिकारी” नाम है जाता।

3. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 5 का संशोधन :—मूल अधिनियम की उपधारा 5 की उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अक्षतस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1-क) बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विभिन्नात्मकरण) अधिनियम, 1978 के विस्तारण की तारों से ही उपधारा (1) के अधीन मारगरीत पर कर उसके विक्रय के पहले प्रक्रम पर उद्यग्हीन किया जाएगा जो प्रक्रम,—

(क) ऐसे व्योहारी को वश में जो बंडीगढ़ संघ राज्यक्रम से बाहर के कितौ स्थान से बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में मारगरीत लाता है, विक्रय का यह प्रक्रम होगा जब ऐसा व्योहारी बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर पहली बार मारगरीत का विक्रय करता है;

(ब) ऐसे व्योहारी को वश में जो बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर मारगरीत करता है, विक्रय का यह प्रक्रम होगा जब ऐसा व्योहारी बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पहली बार मारगरीत का विक्रय करता है,

(ग) किसी अन्य व्योहारी को वश में जिसने पूर्ववर्ती रूप से निर्विष्ट व्योहारी से मारगरीत का कर लही किया है, वह प्रक्रम होगा जिस पर ऐसा व्योहारी बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पहली बार मारगरीत का विक्रय करता है:

परन्तु पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर मारगरीत के किसी विक्रय को इस अधिनियम के अधीन कर से तब तक सूच प्राप्त नहीं होगी जब तक कि ऐसे पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर विक्रय करने वाला व्योहारी विहित प्रलृप और रोति में उस रजिस्ट्रीकृत व्योहारी द्वारा यथा जिससे मारगरीत कर्ता को गई थी, सम्यकतः भरा गया और हस्ताक्षरित प्रमाणग्रह निर्धारण व्यापिकारी को प्रस्तुत नहीं कर पेता है।

4. 1948 के पंजाब अधिनियम, 46 की धारा 10 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (4) में “जिला उत्पादक और करान्दान अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “जिला उत्पादक और करान्दान अधिकारी” शब्द ऐसे जायेंगे।

5. 1948 के पंजाब अधिनियम में नई धारा 11कक्ष का अस्त-स्थापन—मूल अधिनियम की धारा 11-कक्ष के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तर्स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“11कक्षक का मारगरीत पर कर के कुछ निर्धारणों का पुनर्विभांकन और कुछ निर्धारणों का विभिन्नात्मकरण—

(1) इस अधिनियम में किसी बात के हांसे हुए जो निर्धारण प्राप्तिकारी बंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विभिन्नात्मकरण) अधिनियम 1976 के विस्तारण के पूर्व किए गए ऐसे निर्धारणों पुनर्विभांकन का जो पूर्ववर्ती अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसूची पर्याप्त नहीं है पुनर्विभांकन करेगा और पहले किए गए ग्रामीण का फेरफार या पुनर्विभांकन करने वाला ऐसा ग्रामीण करेगा जो पहले किए गए ग्रामीण की पूर्ववर्ती अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के प्रस्तुप बदलने के लिए आवश्यक हो :—

परन्तु ऐसा श्री धारेश इस धारा के भावान किसी व्योहारी के विषय उसका कुराई के अवधारणा द्वारा किया जाएगा।

(2) किसी व्यायालय या किसी भूम्य प्राधिकारी के तप्रतिष्ठूल किसी निर्णय डिप्री या भादेस में किसी बात के हांते हुए भी किन्तु उपवाया (1) के उपबंधों के अधीन रखते हुए बट्टीगढ़ संबंध राज्य के फैल को पंजाब सावारण विभाय-कर (संगीष्ठन और विभिन्नात्मकरण) अधिनियम 1978 के विस्तारण के पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मारेगान की बाबत किया गया था किंतु जाने के लिए लालचित किसी कर फैल कोई निर्धारण पुनः निर्धारण उद्गत हुआ संग्रहण भी नहीं। इसके बावजूद निर्धारण उद्गत हुआ संग्रहण के संबंध में जो गई थी को जाने के लिए लालचित कोई कार्रवाई या बात उन्होंने ही विधिवाच्य और प्रभावों होगी मानो ऐसे निर्धारण पुनः निर्धारण उद्गत हुआ संग्रहण या कार्रवाई मा बात पंजाब माध्यारण विकार-कर (संग्रहण और विभिन्नात्मकरण) अधिनियम 1978 द्वारा यथा संवीधित इस अधिनियम के प्रभावों से गई थी।

(3) संवेदी को हुर करते के लिए यह धोषित कि जाता है फिर उपषाण (2) की किसी बात का यद मर्यान नहीं नयायों लाएगा कि यह फिसी धर्म किस को—

(क) इस अधिनियम और उसके प्रश्नोत बताए गए नियमों के उल्लंघनों के अनुसार किसी प्रवासि के लिए मारगरीत पर कर का निष्पत्ति पुनः निष्पत्तिरिक्त उद्यग्यहण या संप्रयत्न को प्रस्तुत करने से हो।

(अ) पंजाब माधारण विक्रय-कर (मंगोलियन और प्रिंसिपल्सकरण) प्रविनियम 1978 द्वारा यथा संसोधित प्रविनियम के अधीन उससे गोप्य रकम से प्रधिक उसके द्वारा संकेत किसी कर के प्रतिवाय का रद्देबा करने से निवारित करता है।<sup>14</sup>

6. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 14-वी का संशोधनः—  
मूल अधिनियम की धारा 14-वी ही उपर्याय (6) के पश्चात् में “जिता का उत्पादशुल्क और कर अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “हिना का भारताधिक उत्पादक उत्पादशुल्क और कराराधान आयकर” शब्द रखे जाएंगे।

7. 1948 के पंजाब अधिनियम 48 की धारा 23 का मेरिन्डनः मूल अधिनियम को धारा 23 की उपधारा (2) "उत्तराखण्डक और कराधान अधिकारी के रेक को योद्धों के स्थान पर उत्तराखण्डक और कराधान अधिकारी से प्रतिनियन रेक का" एवं राज्य जारी।

उपार्थ—५

चंद्रीगढ़ सम्बन्धीय क्षेत्र को यथा विस्तारित प्रजात भाष्टारण विक्रमप-क्षर (हस्तरा संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का प्रजात अधिनियम संख्या 26)

## ਪੰਜਾਬ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿਨੈਨੀ-ਕਰ ਅਧਿਨਿਧਿਮ, 1948 ਦਾ ਸੰਸਾਂਧਾਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਲਿਏ ਅਧਿਨਿਧਿਮ

भारत गणराज्य के उन तीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा सिम्बोलिक रूप से यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब माध्यारण विकास-कर्त्ता (हितीय मंशोधन) अधिनियम, 1978 है।

(2) अंडीगढ़ संघ राज्य धेत्र को यथा विस्तारित पंजाब साधारण विक्रम-कर प्रधिनियम, 1948 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल प्रधिनियम कहा गया है) धारा 11 की उपाधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपरायी रूपी आमी घर्याह—

"(7) इस अधिनियम के अधीन देय किसी का आरोपण मा  
न्याग की रूप सा घटावी हाल उस सारित्व तक जो अधिरिण

प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी की गई सूचना में यिनिविष्ट की जाए, विहित रीति में संवाध किया जाएगा और इस प्रकार यिनिविष्ट तारीख ऐसी सूचना की सामीक्षा की तारीख से पहले दिन से अन्वन्त और सीम दिन से अनधिक<sup>1</sup> नहीं होगी :

परस्तु निर्धारण प्राधिकारी, जिसे को भारतसाधक सहायक उत्पाद-शृंखला और कराधान आयुक्त के पुर्वानुमोदन से ऐसे संदाय की तारीख को बड़ा समेंगा या ऐसे संदाय को समृद्धित प्रतिभूति या ऐसे प्रत्यामूर्ति पर किसी भी भाग अन्तर्गत कर सकेंगा ।

3. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा II-य का भेदोन्नेत्र : मूल अधिनियम की धारा II-य से "अधिगोपित शास्ति" और "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के बीच से "या द्वेष व्याज" शब्दों का लोप किया आया ।

4. 1948 के पंजाब संविधानियम 46 में नई धारा II-घ की ग्राम स्थापन : धारा II-घ के पश्चात् निम्नस्थिति धारा अन्त्यापिल की जाएगी, पर्याप्त :—

“II-व (1) व्याख्या संदायः यदि कोई व्योहारी धारा 10 की उपशारा (4) की अपेक्षागुस्तार उससे शोध्य कर की रकम का संदाय करने में असफल रहेगा तो वह कर की रकम के प्रतिरिक्षण उससे शोध्य कर की रकम पर उप धारा की उपशारा (3) के विवरणों के प्रस्तुत किए जाने के प्रतिनिम सारीख के ठीक बाब की नारीख से 1 प्रतिशत प्रतिमास की दर पर, एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् इन प्रतिशत प्रतिमास की दर से, व्यक्तिरकम आम् रहने तक, कर की रकम पर साधारण व्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) यदि मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिकारी द्वारा देय कर या शास्त्र की रकम का संदाय नहीं किया जाता है या, यदि ऐसी कोई अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है, वही ऐसी सूचना की तारीख संतुली दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो अधिकारी, कर या शास्त्र की रकम के अतिरिक्त, उग्र तारीख के ठीक बाद की तारीख से जिन पर मध्यस्थिति, सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि या तीस दिन की अवधि समाप्त होती है, एक प्रतिशत प्रतिमास की दर पर, एक मास की अवधि के लिए और तत्परतात् उड़े प्रतिशत प्रतिमास की दर से, अतिक्रम आत्, रद्द करने तक, कर की रकम पर साधारण ज्याज का संदाय करने वाला होता ।

परन्तु जहाँ किसी कर या शास्ति की क्षमता किसी न्यायालय के भावेश द्वारा स्थगित कर दी जाती है, यहाँ 'कर' या शास्ति की रकम स्थगत आवेदन रद्द कर दिया जाने के पश्चात् उभ रकम पर जो अस्तित्व देख पायी जाती है, पूर्वोक्त दर पर अवाज सहित अभूत्ताप होगी और ऐसा अवाज उभ तांत्रिक से जिगको कर या शास्ति पहली बार देख होनी वै संक्षेप होगा ।

( 3 ) इस घारा के अधीन सदैय व्याप्र की रकम--

(i) किमी मास के भाग को एक मास और सौ रुपए से कम रकम को सीधा ए मानकर संर्गति बो आयी:

(ii) संग्रहण और वसुन्धरी के प्रयोगों के लिए इस अधिनियम के सभी उत्तर समर्पण जापानी।

(iii) इस अधिनियम के अधीन अतिरोपित गांव, यादि कोई दो के अधिकार दाता है। ।।

**स्पष्टीकरण :**—गदि कर को रक्षा का कोई स्वायत्त किसी व्यौहारी द्वारा चेक से फिल्म भाला है और उसका संवेदन वैक द्वारा भालार कर दिया जाता है तो उस उभ व्यौहारी की ओर से कर की रक्षा का संवाय करने में असफल रहने की कोहिं भी आवश्यक।

5. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 12 का प्रतिस्थापन मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात् :—

“12-(1) प्रतिदाय :—निर्धारण प्राधिकारी विहित रीत में इस नियमित अवैदन करने वाले किसी रजिस्ट्रीकूट व्यौहारी को उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदर्भ किसी कर, व्याज या शास्ति की रकम का प्रतिदाय तब करेगा;

(क) यदि इस प्रकार संदर्भ कर, शास्ति या व्याज की रकम इस अधिनियम के अधीन उससे शायद रकम से अधिक है, या

(ख) यदि इस प्रकार संदर्भ कर की रकम किसी घोषित माल के विक्रय या क्रेय की वावत है और ऐसा माल या तो प्रतिदाय बाउचर द्वारा या किसी अन्य अवधि की वावत व्यौहारी से शोध रकम के साथ इस प्रकार संदर्भ रकम का समायोजन करके व्यौहारी के विकल्प पर, अन्तर्राजिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम से विक्रीत किया जाता है;

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन प्रतिदाय ऐसी शर्तों के जो विहित की जाए, अधीन होगा;

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई प्रतिदाय तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिदाय के लिए दावा उस तारीख से जिसको ऐसा दावा प्रतिभूत होता है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर न किया गया होगा।

स्पष्टीकरण :—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “अन्तर्राजिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में” पद का वही अर्थ होगा जो इसे केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 में समन्वेशित है।

(2) उपधारा (1) में किसी वात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी सर्वप्रथम प्रतिदाय की जाने वाली रकम की ऐसे समायोजन की तारीख पर व्यौहारी से देते किसी रकम की वसूली के मद्दे सामग्रीजित करेगा और तत्पश्चात् प्रतिशोष, यदि कोई हो, का प्रतिदाय करेगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के आधार पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिदाय किए जाने के लिए अपेक्षित किसी रकम के आदेश को तारीख के नवें दिन के भीतर उसे प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो व्यौहारी उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख की ठीक अगली तारीख से एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से, एक मास के लिए और तत्पश्चात् प्रतिदाय किए जाने तक डेंग प्रतिशत प्रतिमास की दर पर ऐसी रकम पर साधारण व्याज प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु व्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी मास के भाग को एक मास माना जाएगा और सौ रुपए से कम रकम को सौ रुपए माना जाएगा।

(4) यदि नवें दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर प्रतिदाय अनुज्ञात करने में विलंब ऐसे कारण से है जो निर्धारण प्राधिकारी के नियंत्रण से परे है या जो पूर्णतः या भागतः व्यौहारी द्वारा किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसे विलंब की अवधि की उस अवधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके लिए व्याज महात्मा है।

(5) यदि इस वारत में कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई अवधि उपधारा (4) के अधीन व्याज की संगणना के प्रयोजनों के लिए अपवर्जित किया जाता है तो यह प्रश्न असुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, जिसका विनियोग अन्तिम होगा।

(6) जहां प्रतिदाय अनुज्ञात करने वाला आदेश किसी अपील या अपियम कार्यवाहियों की सामग्री है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों लिखित है और निर्धारण प्राधिकारी की यह राय है कि प्रतिदाय ते वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां निर्धारण प्राधिकारी प्रतिदाय को विधारित कर सकेगा और मामले को असुक्त निर्देशित करेगा जिसके आदेश अन्तिम हों।

(7) वह अवधि जिसके द्वारा उपधारा (6) के अधीन विधारित रहेगा इस धारा के अधीन व्याज की संगणना के प्रभीजन के लिए अपवर्जित कर दी जाएगी।

6. 1948 के पंजाब अधिनियम, 46 की धारा 13 को संशोधन,—मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में, “दस रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पचास रुपए” शब्द रखा जाएगे।

7. 1948 के पंजाब अधिनियम, 46 की धारा 27 का संशोधन,—मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) कर, शास्ति या व्याज के संदाय की रीत।”

[फा. सं पू-11015/6/88-यू दी एल]

प्रशोक नाय, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st Nov., 1988

### NOTIFICATION

G.S.R. 1052 (E):—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1956), the Central Government hereby extends to Union territory of Chandigarh, the enactments specified in column (1) of the Schedule hereto annexed, as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the modifications specified in the corresponding entries in column (2) of the Schedule.

### THE SCHEDULE

Enactment	Modifications
(1)	(2)
1. The Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1973 (Punjab Act No. 14 of 1973).	1. In section 2 for the words and figures “the Punjab General Sales Tax Act, 1948”, the words and figures “the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh,” shall be substituted.
2. Section 3 shall be omitted.	
2. The Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1973 (Punjab Act No. 29 of 1973).	In section 2, for the words and figure “the Punjab General Sales Tax Act, 1948”, the words and figures “the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh,” shall be substituted.

1	2	1	3
3. The Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1976 (Punjab Act No. 11 of 1976).	<p>1. In section 1, sub-section (2) shall be omitted.</p> <p>2. In section 2,—</p> <p>(i) for the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh," shall be substituted; and</p> <p>(ii) the words "and shall always be deemed to have been" shall be omitted.</p> <p>3. In section 3, the words "and shall always be deemed to have been" shall be omitted.</p> <p>4. Sections 4 and 5 shall be omitted.</p>		<p>(Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.</p> <p>5. Sections 8 and 9 shall be omitted.</p>
4. The Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 (Punjab Act No. 2 of 1978).	<p>1. In section 1, sub-section (2) shall be omitted.</p> <p>2. In section 2, for the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.</p> <p>3. In section 3,—</p> <p>(i) for the words and figures "the 1st day of April, 1973," the words and figures "the date of extension of the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union territory of Chandigarh," shall be substituted; and</p> <p>(ii) for the word "State" wherever it occurs, the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.</p> <p>4. In section 5, for the words, brackets and figures "before the commencement of the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978" wherever they occur, the words, brackets and figures "before the extension of the Punjab General Sales Tax</p>	<p>1. In section 1, sub-section (2) shall be omitted.</p> <p>2. In section 2, for the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.</p> <p>3. In section 5, for the words "State Government", the words "Administrator appointed by President under article 239 of the Constitution" shall be substituted.</p> <p>4. Section 8 shall be omitted.</p>	

## ANNEXURE-I

## THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) ACT, 1973 (PUNJAB ACT NO. 14 OF 1973) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1973.

2. Amendment of section 4 of Punjab Act XLVI of 1948.—In the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh, in section 4, in sub-section (5),—

(i) in clause (bb), for the figure and word "25,000 rupees" the figure and word "40,000 rupees" shall be substituted; and

(ii) in clause (d), for the figure and word "40,000 rupees" the figure and word "1,00,000 rupees" shall be substituted.

## ANNEXURE-II

## THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 1973 (PUNJAB ACT NO. 29 OF 1973) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1973.

2. Insertion of new section 3A in Punjab Act XLVI of 1948.—In the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh, after section 5, the following section shall be inserted, namely :—

“3A Levy of additional Tax.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be levied and collected on the taxable turnover of a dealer, an additional tax which shall be calculated at the rate of two per centum of the tax payable by him under this Act :

Provided that the aggregate of the tax and surcharge payable under this Act, shall not exceed in respect of goods declared to be of special importance in inter-State trade or commerce by section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, the rate fixed by section 15 of that Act.

(2) Except as otherwise provided in sub-section (1), the provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the additional tax leviable under sub-section (1) as they apply in relation to the tax leviable under any other provision of this Act.”

#### ANNEXURE-III

#### THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1976 (PUNJAB ACT NO. 11 OF 1976) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1976.

2. Amendment of section 5 of Punjab Act 46 of 1948.—In section 5 of the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), in the first proviso, the word “luxury” shall be omitted.

3. Amendment of Schedule A appended to Punjab Act 46 of 1948.—In Schedule A appended to the principal Act, the word “LUXURY” shall be omitted.

#### ANNEXURE-IV

#### THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1978 (PUNJAB ACT NO. 2 OF 1978) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978.

2. Amendment of Punjab Act 46 of 1948.—In the Punjab General Sales Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh, (hereinafter referred to as the principal Act), for the words “Assistant Excise and Taxation Officer” wherever occurring the words “Excise and Taxation Officer” shall be substituted.

3. Amendment of section 5 of Punjab Act 46 of 1948.—In section 5 of the principal Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(1-B) On and with effect from the date of extension of the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union Territory of Chandigarh, tax on margarine under sub-section

(1) shall be levied at the first stage of sale thereof which stage shall,—

(a) in the case of a dealer who brings into the Union Territory of Chandigarh margarine from any place outside the Union Territory of Chandigarh, be the stage of sale when such dealer sells margarine in the first time within the Union Territory of Chandigarh;

(b) in the case of a dealer who manufactures margarine within the Union Territory of Chandigarh be the stage of sale when such dealer sells margarine for the first time in the Union Territory of Chandigarh; and

(c) in the case of any other dealer who has not purchased margarine from the dealer referred to in the preceding clause, be the stage at which such dealer sells margarine for the first time in the Union Territory of Chandigarh :

Provided that no sale of margarine at a subsequent stage shall be exempted from tax under this Act unless the dealer effecting the sale at such subsequent stage furnishes to the assessing authority in the prescribed form and manner a certificate duly filled and signed by the registered dealer, from whom the margarine was purchased.”.

4. Amendment of section 10 of Punjab Act 46 of 1948.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (4), for the words “District Excise and Taxation Officer”, the words “District Excise and Taxation Office” shall be substituted.

5. Insertion of new section 11-AAAA in Punjab Act, 46 of 1948.—After section 11-AAA of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

“11.AAAA Review of certain assessments of tax on margarine and validation of certain assessments.—

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the assessing authority shall review such assessments, reassessments made before the extension of the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union Territory of Chandigarh, as are not in conformity with the provisions of this Act as amended by the aforesaid Act; Act, and make such order varying or revising the order previously made as may be necessary for bringing the order previously made into conformity with the provisions of this Act as amended by the aforesaid Act :

Provided that no order shall be made under this section against any dealer without giving him an opportunity of being heard.

(2) Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court or other authority to the contrary but subject to the provisions of sub-section (1), any assessment, reassessment, levy or collection of any tax in respect of margarine made or purporting to have been made, and any action or thing taken or done or purporting to have been taken or done in relation to such assessment, reassessment, levy or collection under the provisions of this Act before the extension of the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union Territory of Chandigarh, shall be as valid and effective as if such assessment, reassessment, levy or collection or action or thing had been made, taken or done under this Act as amended by the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978.

(3) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in sub-section (2) shall be construed as preventing any person—

(a) from questioning in accordance with the provisions of the Act and Rules made thereunder, the assessment, reassessment, levy or collection of tax on margarine for any period, or

(b) from claiming refund of any tax paid by him in excess of the amount due from him under the Act as amended by the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978.”.

6. Amendment of section 14-B of Punjab Act, 46 of 1948.—In section 14-B of the principal Act, in the proviso to sub-section (6), for the words “Excise and Taxation Officer of the district”, the words “Assistant Excise and Taxation Commissioner in-charge of the district” shall be substituted.

7. Amendment of section 23 of Punjab Act 46 of 1948.—In section 23 of the principal Act, in sub-section (2), for the words “of the rank of Excise and Taxation Officer”, the words “not below the rank of Excise and Taxation Officer” shall be substituted.

#### ANNEXURE-V

#### THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 1978 (PUNJAB ACT NO 26 OF 1978) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1978.

2. In the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as extended to the Union Territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), in section 11, for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(7) The amount of any tax, penalty or interest payable under this Act shall be paid by the dealer in the manner prescribed by such date as may be specified in the notice issued by the assessing authority for the purpose and the date so specified shall not be less than fifteen days and not more than thirty days from the date of service of such notice :—

Provided that the assessing authority may, with the prior approval of the Assistant Excise and Taxation Commissioner, in-charge of the district, extend the date of such payment or allow payment by instalments against an adequate security or Bank guarantee.”.

3. Amendment of section 11-B of Punjab Act 46 of 1948.—In the principal Act, in section 11B, between the words “penalty imposed” and “under this Act” the words “or interest payable” shall be inserted.

4. Insertion of new section 11-D in Punjab Act, 46 of 1948.—After section 11-C, the following section shall be inserted, namely:—

“11-D Payment of Interest.—(1) If any dealer fails to pay the amount of tax due from him as required by sub-section (4) of section 10, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due from him at the rate of one per centum per month from the date immediately following the last date for the submission of the return under sub-section (3) of that section, for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half per centum per month till the default continues.

(2) If the amount of tax or penalty due from a dealer is not paid by him within the period specified in the notice of demand or, if no period is specified, within thirty days from the service of such notice, the dealer shall in addition to the amount of tax or penalty, be liable to pay simple interest on such amount at the rate of one per centum per month from the date immediately following the date on

which the period specified in the notice or the period of thirty days, as the case may be, expires, for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half per centum per month till the default continues;

Provided that where the recovery of any tax or penalty is stayed by an order of any court, the amount of tax or penalty shall, after the order of stay is vacated, be recoverable along with interest at the aforesaid rate on the amount ultimately found to be due and such interest shall be payable from the date the tax or penalty first became due.

(3) The amount of interest payable under this section shall—

- (i) be calculated by considering part of a month as one month and any amount less than one hundred rupees as one hundred rupees;
- (ii) for the purposes of collection and recovery, be deemed to be tax under this Act :
- (iii) be in addition to the penalty, if any, imposed under this Act.”.

Explanation.—If payment of the amount of tax is made by any dealer through cheque and the same is dishonoured by the bank concerned it will amount to failure on the part of the dealer to pay the amount of tax.

5. Substitution of section 12 of Punjab Act 46 of 1948.—In the principal Act, for section 12, the following section shall be substituted, namely :—

“12 Refund.—(1) The assessing authority shall in the prescribed manner refund to a registered dealer applying in this behalf any amount of tax, interest or penalty paid by such dealer under this Act,—

- (a) if the amount of tax, penalty or interest so paid is in excess of the amount due from him under this Act; or
- (b) if the amount of tax so paid is in respect of the sale or purchase of any declared goods and such goods are sold in the course of inter-state trade or commerce, either by a refund voucher or, at the option of the dealer by adjustment of the amount so paid with the amount due from him in respect of any other period ;

Provided that the refund under clause (b) shall be subject to such conditions, as may be prescribed:

Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of three years from the date on which such claim accrues.

Explanation.—For the purposes of this sub-section the expression “in the course of inter-State trade or commerce” shall have the meaning assigned to it by section 3 of the Central Sales Tax Act, 1956.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the assessing authority shall first adjust the amount to be refunded towards the recovery of any amount due from the dealer on the date of such adjustment, and shall thereafter refund the balance, if any.
- (3) Where any amount required to be refunded by the assessing authority to any person by virtue of an order issued under this Act is not refunded to him within ninety days of the date of the order, the dealer shall be entitled to get simple interest on such amount at the rate of one per centum per month from the date immediately following the date of expiry of the said period for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half per centum per month till the refund is made: Provided that for the purpose of calculation of the interest, part of a month shall be considered as one month and any amount less than one hundred rupees shall be considered as one hundred rupees.

(4) If the delay in allowing refund within the aforesaid period of ninety days is for reasons beyond the control of the assessing authority or attributable to the dealer, whether wholly or in part, the period of such delay shall be excluded from the period for which interest is payable.

(5) If any question arises whether any period is to be excluded for the purposes of calculation of interests under sub-section (4) the same shall be referred to the Commissioner or such other officer as the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution may, by notification, appoint, whose decision shall be final.

(6) Where an order allowing refund is the subject matter of an appeal or further proceedings or where any other proceedings under this Act are pending, and the assessing authority is of the opinion

that the refund is likely to adversely affect the recovery, the assessing authority may withhold the refund and refer the case to the Commissioner whose orders shall be final.

(7) The period during which the refund remains withheld under sub-section (6) shall be excluded for the purpose of calculation of interest under this section."

6. Amendment of section 13 of Punjab Act 46 of 1948.— In the principal Act, in section 13, in sub-section (2), in clause (a), for the words "ten rupees", the words "twenty-five rupees" shall be substituted.

7. Amendment of section 27 of Punjab Act 46 of 1948.— In the principal Act, in section 27, in sub-section (2), after clause (i), the following clause shall be inserted namely:—

(ii) the manner of payment of tax, penalty or interest".

[No. U-11015/6/82-UTL]

ASHOK NATH, Lt. Secy.

